

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० ७२]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च १०, १९७२/फाल्गुन २०, १८९३

No 72]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 1972/PHALGUNA 20, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi. the 9th March 1972

G.S.R. 97(E).—The following Proclamation by the President is published for general information:—

Whereas I, V. V. Giri, President of India, am satisfied that a situation has arisen in the State of Bihar in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

- assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;
- declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and
- make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of the Proclamation, namely:—
 - in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the Report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor General of India; articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;

article 167;

so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;

articles 174 to 178 (both inclusive);

clauses (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article;

articles 180, 181 and 182, clause (c) of article 183 and the proviso thereto;

article 185;

so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;

articles 189, 193 and 194;

so much of article 195 as relates to the salaries and allowances of Members of the Legislative Assembly;

articles 196 to 198 (both inclusive), clauses (3) and (4) of article 199;

so much of sub-clause (b) of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;

articles 208 to 211 (both inclusive);

the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference thereon to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the reference in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall be construed as references to the President and to Parliament or to the Houses thereof respectively:

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to much extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

(iv) any reference in the Constitution to Acts or laws of, or made by, the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or Laws made in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Bihar and Orissa General Clauses Act, 1917 (Bihar and Orissa Act 1 of 1917), as in force in the State of Bihar, and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1972

अधिनूचना

जी० एस० आर०—97(अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्व-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है :—

अतः, मुझे, १० वे० गिरि, भारत के राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो गया है कि बिहार राज्य में ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कि उस राज्य का शासन भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'संविधान' कहा गया है) के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है :

अतः अब मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उद्घोषणा करता हूँ कि मैं—

- (क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित, या एतद्द्वारा सभी शक्तियाँ, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने हाथ में लेता हूँ ;
- (ख) घोषित करता हूँ कि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियाँ संसद के प्राधिकार द्वारा या अधीन प्रयो तब्य होंगी ; और

- (ग) निम्नलिखित आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध करता हूँ जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं, अर्थात्:—

- (i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खंड (क) के आधार पर अपने हाथ में लिए गए कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझूँ उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा ;

- (ii) उस राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के प्रवर्तन को एतद्द्वारा निलम्बित किया जाता है, अर्थात् —

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडल को निर्देश करने से है ;

अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है ;

अनुच्छेद 163 और 64 ;

अनुच्छेद 166 के खंड (3) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य सरकार के कार्य के मंत्रियों के बीच बंटवारे से है ;

अनुच्छेद 167 ;

अनुच्छेद 169 के खंड (1) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प पारित किए जाने से है ;

अनुच्छेद 174 से 178 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) ;

अनुच्छेद 179 का खंड (ख) और (ग) और उस अनुच्छेद का प्रथम परन्तुक ;

अनुच्छेद 180, 181 और 182, अनुच्छेद 183 का खंड (ग) और उक्त परन्तुक ;

अनुच्छेद 185 ;

अनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के सम्बन्धों और भक्तों से है ;

अनुच्छेद 189, 193 और 194 ;

अनुच्छेद 195 का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के सदस्यों के सम्बन्धों और भक्तों से है ;

अनुच्छेद 196 से 198 तक (जिनमें ये दोनों सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 199 के खंड (3) और (4) ;

अनुच्छेद 202 के खंड (3) के उप-खंड (ख) का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के सम्बन्धों और भक्तों से है ; अनुच्छेद 208 से 211 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) ;

अनुच्छेद 213 के खंड (1) का परन्तुक और खंड (3) का परन्तुक ; और

अनुच्छेद 323 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध जापन सहित रिपोर्ट को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है ;

- (iii) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ उस राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जायेगा और उसमें राज्य के विधान मंडल या विधान सभा के प्रति किसी निदेश का जहां तक उसका संबंध उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है, अर्थ, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो संसद के प्रति निदेश लगाया जाएगा और विशिष्टतया अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधान मंडल या विधान सभा के प्रति निदेश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति और संसद या उसके सदस्यों के प्रति निदेश लगाया जाएगा ;

परन्तु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से लेकर पैरा 4 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी और न राष्ट्रपति को उस खण्ड के उपखण्ड (1) के अधीन उस सीमा तक जहां तक वह ठीक समझे उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी ;

- (iv) संविधान में राज्य के विधान मंडल के या एतद्वारा बनाए गये अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निदेश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानों उसके अन्तर्गत इस उद्घोषणा के आधार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निदेश है, और बिहार और उड़ीसा साधारण खण्ड अधिनियम 1917 (1917 का बिहार और उड़ीसा अधिनियम 1), जिस रूप में बिहार राज्य में लागू है और साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (1897 का 10 वें), का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लागू है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी होगा मानो यह उस राज्य के विधान मंडल का अधिनियम हो ।

नई दिल्ली,
दिनांक 9 मार्च, 1972

ब० वे० गिरी,
राष्ट्रपति ।

[सं० फा० 38/21/71-पील० I (ए०)]

ORDER

New Delhi, the 9th March 1972

G.S.R. 98(E). The following Order by the President is published for general information:—

In pursuance of sub-clause (1) clause (c) of the Proclamation issued on this the 9th day of March, 1972, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Bihar and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State

NEW DELHI;
The 9th March, 1972

V V GIRI,
President

[No. F 38 21 71-Pol II(A)]

NEW DELHI;
The 9th March 1972

GOVIND NARAIN, Secy

आदेश

नई दिल्ली 9 मार्च 1972

जी एस०आर० 98 (अ) --राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है --

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज मार्च 1972 के 9वें दिन जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) का अनुसरण करते हुए मैं एतद्वारा निदेश देता हूँ कि बिहार राज्य सरकार के सभी कर्तव्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रचलित किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल से निहित या प्रयोज्य सभी शक्तियाँ जिनका राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खण्ड (क) के आधार पर अपने हाथ में ले लिया है राष्ट्रपति के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोज्य होंगी।

नई दिल्ली
9 मार्च 1972

ब० व० गिरी
राष्ट्रपति।

[संख्या फा० 38 21 71-पाल० I (प) I]

नई दिल्ली
9 मार्च 1972

गोविन्द नारायण,
सचिव।

